मानसून के कहर के बाद टूटी आपदा प्रबंधन तंत्र की नींद

- नुकसान हुआ तो सक्रिय हुए मंत्री और अफसर
- देहरादून से लेकर दिल्ली तक घनघनाते रहे फोन
- भारी बरसात से 2011 में भी हुआ था खासा नुकसान

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। रविवार को जब मानसून ने प्रदेश में कहर बरपाया तब आपदा प्रबंधन तंत्र की नींद टूटी। भारी बरसात के कारण जगह-जगह से आ रही नुकसान की खबरों के बीच दिल्ली से देहरादून तक फोन की घंटियां बजने लगीं। आनन फानन में निर्देश जारी किए गए, अपील की गई और भरोसा दिलाया गया। पिछले साल की तरह ही इस बार भी मौसम की मार पड़ने के बाद राहत और बचाव के लिए समीक्षा करने की बात की जा रही है। स्थिति यह है कि आपदा के इस घड़ी में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जहां दिल्ली में हैं वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल की देहरादून में ही मौजूदगी रही। कृषिमंत्री हरक सिंह रावत भी अपने निर्वाचन क्षेत्र रुद्रप्रयाग की ओर रुख नहीं कर पाए।

शनिवार से शुरू हुई बारिश रविवार को भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। 2011 में भी इसी तरह के हालात बने थे। उस समय प्रदेश में भारी बरसात के कारण पूरे प्रदेश में करीब 14000 किलोमीटर सड़क ध्वस्त हो गई थी। 2012 में उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में आई दैवीय आपदा के कारण करीब 14 से अधिक पुल ध्वस्त हो गए थे। इनका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। 13 जून को ही सरकार ने दैवीय आपदा के तहत जिलाधिकारियों को तीन-तीन करोड़ रुपये जारी किए थे। यही नहीं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने 26 मई से समीक्षाओं का सिलसिला शुरू किया था पर आपदा प्रबंधन को इसमें शामिल नहीं किया गया। आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल आर्य के साथ ही मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी अपने ही विधायकों की नाराजगी से उपजे सियासी तूफान में उलझे रहे और इधर आपदा प्रबंधन तंत्र अपनी सरकारी सुस्त चाल पर बदस्तूर कायम रहा।

रविवार को हालात जब बेकाबू हुए तो मंत्रियों और अफसरों की नींद टूटी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में रहते हुए ही उत्तराखंड में अफसरों से बात की। आनन फानन में सोमवार को आयोजित की जा रही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हालात की जानकारी लेने की तैयारी है। यह समीक्षा भी उस वक्त होगी जब जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी भारी बरसात के कारण बेकाबू होते जा रहे हालात से निपटने की कोशिश कर रहे होंगे। देखते ही देखते आपदा प्रबंधन का सचिवालय में कंट्रोल रूम बना दिया गया और ऊपर से लेकर नीचे तक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल आर्य रविवार को दून में ही थे और उन्होंने भी अधिकारियों से बात की।

यूं हरकत में आई सरकार

- मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दिल्ली से मुख्य सचिव सुभाष कुमार और सचिव आपदा भास्करानंद से जानकारी हासिल की। सोमवार को देहरादून लौटते ही वीडियो कांफ्रेंसिंग कर कमिश्नर व सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा की स्थिति का जायजा लेंगे।
- मुख्यमंत्री ने राजकीय हेलीकाप्टर के साथ ही निजी कंपनियों से भी जरूरत पड़ने पर हेलीकाप्टर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
- मुख्य सचिव ने यात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर ही राज्य की ओर रुख करने और बरसात रुकने पर ही यात्रा पर आने की अपील की।
- जिलाधिकारी चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी को निर्देशित किया गया कि वे सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ समन्वय कर यात्रा मार्गों पर यातायात व्यवस्थित करें। फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें।
- मुख्यमंत्री कार्यालय के तहत सचिवालय में 24 घंटे सक्रिय रहने वाले कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया और अपर सचिव मुख्यमंत्री अमित नेगी को इसका प्रभारी बनाया गया। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को बरसात व भूस्खलन से बंद रास्तों के कारण फंसे यात्रियों को भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।

अपना राज्य, अपनी सरकार, फिर भी ये भगवान भरोसे

- अति संवेदनशील चिह्नित किए गए 233 गांवों का विस्थापन नहीं हो पाया।
- टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले गांवों के विस्थापन का मसला भी अधर में
- उत्तरकाशी में नदी का मलबा बढ़ जाने के कारण अब बाढ़ जैसे हालात ही बन रहे हैं। यहां नदी तल से मलवा न हटने के कारण अब दोगुनी मुसीबत इन सबके सर पर है।
- शहरों में बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। लिहाजा अब जलभराव से सैकड़ों लोगों की जान पर बन आई है।
- चार धाम यात्रा के लिए कोई आकस्मिक प्लान तैयार नहीं किया गया। हालांकि पिछले कुछ सालों से हर बार सरकार को यात्रियों से बरसात के दौरान यात्रा पर न आने की अपील करनी पड़ती है। लिहाजा यात्रा मार्ग पर कई यात्री फंसे हुए हैं।

बरसात के कारण खासे नुकसान की जानकारी मिल रही है। मैंने मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों से भी बात की है। राहत और बचाव कार्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सारे मामले को लेकर बैठक होगी।

-यशपाल आर्य, आपदा प्रबंधन मंत्री

भारी बारिश के चलते दैवीय आपदा से प्रभावितों को हर संभव सहायता देने के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। सीमा सड़क संगठन एवं आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ पूरा समन्वय बना हुआ है। दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं यात्रा मार्गों को खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन के मुख्य अभियंता को मुख्यमंत्री ने दूरभाष पर निर्देश दिए। यात्रा मार्गों पर खाद्यान एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और यात्रा मार्गों के बंद होने के साथ ही उनके खुलने का भी व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं।

- सुभाष कुमार, मुख्य सचिव